



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2014/चैत्र 4, 1936

No. 84] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2014/CHAITRA 4, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2014

जांच शुरुआत

(द्वितीय निर्णायक समीक्षा)

विषय:—चीन जन.गण से विटामिन-ई पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की द्वितीय निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।

एफ सं. 15/31/2013-डीजीएडी—1995 और उसके पश्चात यथासंशोधित सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) चीन जन.गण. में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित “विटामिन-ई, प्राकृतिक रूपों को अपवर्जित करते हुए सभी रूपों” के आयात पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी।

2. यतः, सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या 14/23/2002-डीजीएडी के तहत प्रारंभ की गई थी। प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 02 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना सं.14/32/2002-डीजीएडी के तहत जारी किया गया था और राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 41/2003- सीमाशुल्क के तहत अनंतिम पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था। प्राधिकारी द्वारा दिनांक

22 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं. 14/32/2002-डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना निर्णायक शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हुए जारी की गई। अपने अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं. 145/2003-सीमाशुल्क के तहत एक निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 07 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. 15/10/2008-डीजीएडी के तहत प्रथम निर्णायक समीक्षा प्रारंभ की। उपर्युक्त प्रथम निर्णायक समीक्षा के संबंध में अंतिम जांच परिणाम प्राधिकारी ने दिनांक 05 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. 15/10/2008-डीजीएडी के तहत संस्तुत किए थे। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम में की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. 33/2009-सीमाशुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था और यह पाटनरोधी शुल्क पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी बनाया गया था।

3. यतः मैसर्स मेर्क लिमिटेड ने संबद्ध देशों में उद्भवित या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटन की निरन्तरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति संभावना का आरोप लगाते हुए अधिनियम और नियमों के अनुसार एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया और सम्बद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क के मौजूदा स्वरूप की समीक्षा करने तथा उसमें संशोधन करने एवं उसका विस्तार करने का अनुरोध किया है।

#### घरेलू उद्योग

4. निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदनपत्र मेर्क लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता सम्बद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन के एक बड़े भाग का उत्पादन करता है और इसलिए वह नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

#### विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. मूल जांच की तरह की वर्तमान जांच में भी विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित “प्राकृतिक रुपों का अपवर्जन करके सभी रुपों में विटामिन-ई” है। वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा होने के कारण इस जांच में मूल तथा उत्तरवर्ती निर्णायक समीक्षा जांचों में शामिल उत्पाद को ही कवर किया गया है।

6. उत्पादन विटामिन-ई एसोटेट को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, के अध्याय 29362800 में वर्गीकृत किया गया है और विटामिन-ई (50 प्रतिशत शुष्क पाउडर) फीड ग्रेड को पशुआहार में प्रयोग किए जाने वाले तैयार वस्तुओं के तौर पर 23099010 के रुप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, उपर्युक्त वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रुप में वर्तमान जांच पर बाध्यकारी नहीं है।

#### निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

7. दायर किए गए विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी ने सम्बद्ध देश में उद्भवित यहां वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के बारे में प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के सतत अधिरोपण की जरूरत की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग को

पाटन एवं क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एतद्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करने का निश्चय किया है।

अंतर्ग्रस्त देश

8. इस जांच में अंतर्ग्रस्त देश चीन जन.गण है।

जांच की अवधि (पीओआई)

9. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 01 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 (12 माह) है। तथापि, क्षति जांच अवधि में वर्ष 2010, 2011 और 2012 और जांच की अवधि को शामिल किया जाएगा।

प्रक्रिया

10. इस समीक्षा में दिनांक 05 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. 15/10/2008-डीजीएडी के तहत प्रथम निर्णायक समीक्षा मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं।

11. प्रमुख नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के सभी उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों तथा सम्बद्ध देश की सरकारों को भारत स्थित उनके राजदूतावास के जरिए और भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप और ढंग से सभी संगत जानकारी प्रदान करने के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर प्रेषित करने हेतु अलग से संबोधित किया जा रहा है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा नं. 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110011

13. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी अधोलिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरूप और ढंग में इस जांच से संगत जानकारी का प्रस्तुतिकरण कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष किसी गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले पक्षकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उसका अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराए।

समय-सीमा

14. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई के कोई अनुरोध लिखित रूप में प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे वह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिनों) से अनधिक समय में पहुंच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना

अधूरी है तो प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

15. वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर के संबंध में कि इस पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा जाए या नहीं इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख चालीस (40) दिनों के अंदर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनों रूपों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध करना

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किए जाने के मामले में इसे दो अलग-अलग भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए: (क) गोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठ की संख्या आदि) तथा (ख) दूसरा भाग अगोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि)। उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" लिखा जाना चाहिए।

17. किसी भी तरह के गोपनीय चिह्न के बिना उपलब्ध कराई गई सूचना अगोपनीय समझी जाएगी और प्राधिकारी के अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने का अनुमति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होंगे। गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां तथा अगोपनीय पाठ की पांच (05) प्रति सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

18. गोपनीय के रूप में दावाकृत किसी भी सूचना के लिए सूचना के प्रदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रदत्त सूचना के साथ-साथ उन कारणों का विवरण प्रस्तुत करेगा कि उक्त सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या उक्त सूचना को सारांश रूप में क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है।

19. अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचीबद्ध किया जाए/संक्षेप में बताया जाए। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके। फिर भी, विशेष परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी दर्शा सकती है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और कारणों का एक ब्यौरा कि संक्षेपण संभव क्यों नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए।

20. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के पश्चात् गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीय के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना के सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

21. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में दिए गए कारण के ब्यौरे के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को निर्दिष्ट रिकार्ड में नहीं लेंगे। प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना से संतुष्ट होने और गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार कर लेने पर, ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए बिना, किसी भी पक्षकार के समक्ष इसे प्रकट नहीं करेंगे।

## सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

22. पाटनरोधी अधिनियम के नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

## असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2014

### Initiation

(2nd Sunset Review)

**Subject : Initiation of Second Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on Vitamin-E from China PR.**

**F. No. 15/31/2013-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of “Vitamin-E all forms excluding natural forms” (hereinafter referred as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country).

2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority *vide* Notification No. 14/32/2002-DGAD dated Aug/27/2002. The Preliminary Finding was issued by the Authority *vide* Notification No. 14/32/2002-DGAD dated Dec/02/2002 and the provisional anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue *vide* Notification No. 41/2003-Customs on 7th March 2003. The Final Findings Notification was issued by the Authority *vide* Notification No. 14/32/2002-DGAD dated Aug/22/2003, recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, a definitive anti-dumping duty was imposed the Central Government *vide* Notification No. 145/2003-Customs dated Oct/6/2003 on the imports of the of the subject goods, originating in or exported from the subject country. The designated authority had initiated first sunset review *vide* notification No. 15/10/2008-DGAD dated Mar/7/2008. The final finding with respect to the said first sunset review, the Authority had recommended *vide* Notification No. 15/10/2008-DGAD dated Mar/5/2009. On the basis of this recommendations made by the Authority in the final findings, a definitive anti-dumping duty was imposed the Central Government *vide* Notification No. 33/2009-Customs dated Mar/27/2009 and made the anti-dumping duty effective for a period of five years.

3. Whereas, Merck Limited have filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Subject Country and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

### Domestic Industry

4. The application for the sunset review has been filed by Merck Ltd. As per the information available, the petitioner accounts for a major proportion in Indian production of the subject goods and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.

#### **Product under consideration and Like Article**

5. The product under consideration, in the original as well as the present sunset review investigation, is “Vitamin-E all forms excluding natural forms”, originating in or exported from China PR. The present investigation being a sunset review, the investigation covers the product as in the original and subsequent sunset review investigations.

6. The product Vitamin E-Acetate is classified in Chapter 29362800 of the Customs Tariff Act and Vitamin-E (50% dry powder) feed grade is classified in terms of 23099010 as preparations of a kind used in animal feeding. However, the above classification is indicative only and is no way binding on the investigation.

#### **Initiation of Sunset Review**

7. Whereas, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

#### **Country involved**

8. The country involved in this investigation are China PR.

#### **Period of Investigation**

9. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1st January 2013 to 31st December 2013 (12 months). However, injury analysis shall cover the years as 2010, 2011 and 2012 and the POI.

#### **Procedure**

10. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the 1st SSR original investigation published *vide* Notification No. 15/10/2008-DGAD dated Mar/5/2009.

11. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules *supra* shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

#### **Submission of Information**

12. The known exporters in the subject country, the Government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority**  
**Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties**  
**Ministry of Commerce and Industry**  
**Department of Commerce**  
**Room No. 240, Udyog Bhavan**  
**New Delhi-110011**

13. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

#### **Time Limit**

14. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

#### **Submission of information on confidential basis**

16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page.

17. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

18. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential, version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **Inspection of public file:**

22. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

#### **Non-cooperation**

23. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority